SHRI SHANTI BHUSHAN: Sir, I have already said that if a question relates to a specific grant of a licence in an individual case, I would require specific notice to answer it properly.

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : श्रीमन्, मंत्री जी का यह तो टालने वाला जवाब हुआ। Chairman Saheb, you are the custodian of our rights.

अगर मंत्री इस तरह से जवाब देकर निकल आएंगे तो फिर काम कैसे चलेगा और हम लोग यहां पर क्यों बैठे हुए हैं ? इस प्रश्न का जवाब देने के लिए कहां नोटिस की आवश्यकता है ?

MR. CHAIRMAN: He wants notice.

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : इनके पास फाइल है। उसको देख कर मंत्री जी जवाब दे सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वे कौन-सी परिस्थितियां थी जिनके अन्तर्गत यह लाइसेंस दिया गया है। चेयरमैन साहब, आप हमारे राइट्स को नहीं देखेंगे तो फिर कौन देखेंगा ?

MR. CHAIRMAN: Next question.

Expenditure on the maintenance of the Railway Board

*606. SHRI BHIM RAJ:
SHRI SAWAISINGH SISODIA:
SHRI GURUDEV GUPTA:
SHRI PRAKASH MEHROTRA:†
SHRIMATI HAMIDA HABIBULLAH:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government have recently taken any steps to effect economy in the expenditure incurred in respect of the Railway Board; and

(b) if so, what are the details in this regard?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE): (a) and (b) Yes, Sir. Economy has been effected by restructuring the Board. Other measures have also been taken to reduce expenditure on creation and filling up of posts, travelling and overtime allowances, staff cars, telephones etc.

श्री प्रकाश महरोत्रा : मान्यवर, जिस तरीके से जादूगर हाथ की सफाई दिखलाता है उसी तरीके से मंत्री जी ने उत्तर देने में जवान की सफाई दिखलाई है। उन्होंने यह नहीं बतलाया है कि रेलवे विभाग में कितनी इकनोमी की गई है और इस संबंध में उन्होंने कोई फीगर भी नहीं दी है। जो इकनोमी की गई है उसको गौर से देखने की जरूरत है। जो पोस्ट्स सैंक्शन्ड थी उनको खाली रखा गया है और कुछ पोस्ट्स को एबोलिश कर दिया गया है। कुछ लोग जो छुट्टी में गये थे या ट्रेनिंग में गये थे या डेपुटेशन मे गये थे उनकी जगह पर नियुक्ति नहीं की गई है। इस प्रकार से बचत की गई है। इसी प्रकार से कुछ जो केडर्स थे और जिनके लोअर पे-स्केल थे, उनके एरियर्स के लिए जितना प्रोविजन किया गया था उसमें कुछ कमी हुई है। मैं समझता हूं कि यह जितनी भी सेविंग है यह नेगेटिव सेविंग है। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने पोजिटिव सेविंग कितनी की है, यह आप स्पष्ट तौर पर बताने की कृपा करें। इस नेगेटिव सेविंग का कितना एमाउन्ट है और बाकी कितना एमाउन्ट है, यह आप साफ साफ बताने की कृपा करें।

प्रो० मधु दण्डवते : माननीय सदस्य ने जो जानकारी पूछी है, वह मैं दे सकता हूं। यह जानकारी मेरे पास है। रेलवे बोर्ड की पुनर्रचना करने के बाद जितनी बचत हम लोगो ने की है, वह 1 लाख 44 हजार है। आप उसका ब्रेक-अप चाहते हैं तो वह भी मैं बता सकता हूं और आठ एडीशनल मेम्बर्स पर व्यय 2.88 लाख है। जो पोस्ट्स रेलवे बोर्ड ने एबोलिश किये और

less expenditure on operation of the three Advisors and DGRHS

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Prakash Mehrotra.

क्योंकि तीन एडीशनल मेम्बर को ड्रोप किया गया तो उसके बाद तीन एडवाइजर आए । उसका खर्च 1.44 लाख रुपये आया । इस तरह से कुल मिला 1.44 लाख रुपयों की बचत हुई है । आगे चल कर यह भी बताना चाहता हूं कि सारे देश में जितने वर्किंग एक्सपेंसेज़ हैं उनमें 0.25 % सिर्फ रेलवे बोर्ड पर मुलाज़िमों पर खर्च किया जाता है । मैंने जिक्र किया है जो स्टेप्स हमने लिए हैं, जिनकी वजह से हम सेविंग कर पाए है, उनकी डिटेल्स भी दी है । अगर आप चाहें तो मैं किन कारणों से कितनी बचत हुई है वह भी बता सकता हूं । जहां तक क्रिएशन एंड फिलिंग अप आफ पोस्टस का संबंध है हम रेलवे बोर्ड की कुशलता से 1977–78 में इस साल 45000 रुपये की इकोनोमी कर पाए है । मैंने जिक्र किया कि ट्रेवलिंग अलाउंस के विषय में हम लोगों ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है और खर्च कम कर दिया है । ओवर-टाइम अलाउंस हमको देना पड़ता है तो इन सबमें कुल मिला कर 7 लाख खर्च होता था । इन्सर्फेक्शन यूनिट द्वारा किये गये प्रयत्नों के फलस्वरूप में वह अब 5 लाख रुपये खर्च आया है । तीसरी बात मैं यह बताना चाहता हूं कि स्टाफ कार के बारे में भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं जिस पर 1975–76 में 2.76 लाख रुपये खर्च था वह 2.65 लाख हो गया है । टेलीफोन पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं । इस प्रकार इस विषय में मैं आपको तीन साल की फिगर्स पढ़ कर सुनाना चाहता हूं । 1975–76 में 19.37 लाख, 1976–77 में 18.24 लाख, और 1977–78 में 16.8 लाख रुपये तक खर्च घटा है । कंटेनजेंसीज़ एक्सपेंडीचर में भी इकोनोमी की गई है जो कि 47 लाख रुपये से घटा कर 46 लाख हो गया है । यह हमारा इकोनोमी के बारे में हिसाब है ।

श्री प्रकाश महरोत्रा : मान्यवर, पहलीबात तो यह है कि जो माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है उसमें 25 फिगर्स पढ़ दी है । इस तरह से इतनी फिगर्स कोई भी याद नहीं रख सकता इतनी फिगर्स कोट करना एक अनुचित बात है और यह डेलीब्रेटली की गई है ताकि कोई प्रश्न न पूछा जा सके । पहले से रिटन फिगर्स रिप्लाई में दी जानी चाहिए । मेरे कहने का मतलब यह है कि एक तो उत्तर यह आता है कि सन् 1950–51 में जो लेवल था उससे आज 350 % रेलवे बोर्ड के खर्च में वृद्धि हो गई है । इस बात को माननीय मंत्री जी खुद मानते हैं । इसके दो कारण बताए जाते हैं । एक तो यह कि डवलपमेंटल एक्टीविटीज़ बढ़ गई हैं, दूसरा यह कि पार्लियामेंट के मैम्बरों के क्वेश्चंन और क्वेरीज़ बहुत बढ़ गई है इसलिए रेलवे बोर्ड का खर्च बढ़ गया है । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि पार्लियामेंट के मैम्बर्स के क्वेश्चंस और क्वेरीज़ कितने बढ़े हैं और इस संबंध में कितना खर्च बढ़ा है ?

प्रो० मधु दण्डवते : मान्यवर, रेलवे बोर्ड में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनमें से कुछ लोगों को उत्तर तैयार करने की जिम्मेदारी दी जाती है । इसलिए पार्लियामेंट के क्वेश्चंस कितने बढ़े हैं और उनकी वजह से कितना खर्च बड़ा है, यह स्टेटेस्टिक्स देना मेरे लिए ठीक नहीं होगा । शुरू मे माननीय सदस्य ने कहा कि जो आंकड़े मैंने प्रस्तुत किए हैं वे मूल प्रश्न के उत्तर में होते तो ज्यादा अच्छा होता लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि फिर टेबल पर रखने की जरूरत नही है । जब मैंने आंकड़े पढ़ दिए हैं तो वे सभा के रिकार्ड में आ जाएंगें और . . .

श्री प्रकाश महरोत्रा : माननीय मंत्री जी अगर आंकड़े इसी तरह पढ़ेंगे तो और 25–30 फिगर्स दे देंगे तो उस पर सप्लीमेंटरी कैसे पूछा जा सकता है । यह सब सप्लीमेंटरी अवायड करने के लिए है ।

प्रो० मधु दन्डवते : मैंने जो आंकड़े कोट किए हैं वे बहुत ही तेज रफ्तार के साथ नहीं पढ़े है । मैं समझता हूं उसको पिक-अप करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ।

अब आपके सामने पूरक प्रश्न पूछने के लिए नहीं है तो प्रश्न मैं क्या करूं ।

श्री प्रकाश महरोत्रा : प्रश्न तो मेरे सामने हैं .... *(Interruptions)*

SHRIMATI HAMIDA HABIBULLAH: Sir the original idea was that the Indian Railways would be one integrated unit controlled by the Railway Board, but with the re-introduction of the various railway companies, the Board has long been totally redundant with the Railway Ministry sitting on top of the Railway Board's head. Will the hon. Minister be so good as to examine and rectify what is not only a waste of public and railway revenues, in my opinion, but which makes the whole organisational set-up hopelessly unmanageable?

PROF. MADHU DANDAVATE: There can be two honest opinions about this point. In fact, the very structure of the Railway Board, unlike some other sector is such that the entire membership of the Railway Board is drawn from those who are working in the field as General Managers. And they come from various disciplines like, civil engineering, traffic, finance, and all that. Since such functional organisers come to the Railway Board, the Railway Board really becomes not purely an administrative body but a functional body, equipped with the knowledge of almost all the disciplines. I think it is not a demerit but merit of the construction of the Railway Board.

SHRI ANANT PRASAD SHARMA: It is always said that as an economy measure they are cutting the expenditure. This kind of a reorganisation is done in respect of the Railway Board only. May I know whether this aspect is also taken into account in the working of the whole railways in view of the fact that the work-load of the railways is increasing, before taking this step?

PROF. MADHU DANDAVATE: Yes, Sir, that is also borne in mind and only after that the necessary economies are effected.

MR. CHAIRMAN: Question Hour Over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Purchase of Hessian bags by the Nangal Fertilizer unit

*601. SHRI SUJAN SINGH: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) the details of the purchases made by the Fertiliser Unit at Nangal in Punjab, in respect of the Hessian and H.D.P. bags during the last three years;

(b) the rates quoted by each dealer and the names of dealers who were given contract for the supply of these bags;

(c) what are the terms and conditions prescribed by the said unit for the purchase of such bags;

(d) whether it has been brought to Government's notice that under the present terms and conditions a small scale businessman cannot afford to supply these items; and

(e) whether Government propose to issue instructions to the said unit to review these conditions with a view to making it possible for the small scale sector to supply such bags; if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) to (e) A statement is laid on the Table of the House.